

हसि्टरेक्टमी

प्रलिस के लयः

हसि्टरेक्टमी, अनुच्छेद 21

मेन्स के लयः

महला सवासुथय के मुददे और संबंघतऱ उपाय, मातृ सवासुथय का महत्त्व

चर्चा में क्यौं?

भारत सरकार के सवासुथय और परवार कल्याण मंत्रालय ने गरीब और कम शकषतऱ महलाओं, वशष रूप से ग्रामीण कषेत्रों में, जो कऱ अनुचतऱ हसि्टरेक्टमी प्रकुरयऱ से गुज़रती हैं, के उच्च जोखमऱ के मुददे के समाधान हेतु उपाय शुरू कयऱ हैं ।

हसि्टरेक्टमी:

परचयः

- हसि्टरेक्टमी एक सर्जकऱल/शल्य प्रकुरयऱ है, जसऱमें गर्भाशय (गर्भ), एक महला के शरीर का वह अंग जहाँ गर्भावसुथा के दौरान एक बच्चा वकऱसतऱ होता है, को हटाना शामिल है ।

प्रकारः

- जब केवल गर्भाशय को हटायऱ जातऱ है, तो इसे आंशकऱ (Partial) हसि्टरेक्टमी कहा जातऱ है । जब गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटा दयऱ जातऱ है, तो इसे पूरण (Total) हसि्टरेक्टमी कहा जातऱ है ।
- जब गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योना कऱ हसऱसा और इन अंगों के आस-पास के सनायुबंधन एवं ऊतकों का एक वसऱतृत कषेत्र हटा दयऱ जातऱ है, तो इसे रेडकऱल हसि्टरेक्टमी कहा जातऱ है ।

भारत में हसि्टरेक्टमी के संकेतकः

- फाइब्रॉएड (गर्भ में या गर्भ के आसपास गैर-कैंसर वृद्धऱ), एंडोमेटुरयऱसऱसऱ (ऐसी बीमारऱ जसऱमें गर्भाशय कऱ लनऱगऱ के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर वृद्धऱ कऱरतऱ है), असामान्य रक्तस्राव और शरोणा सऱजन कऱ बीमारऱ जैसी स्तुरी रोग संबंघी सुथतऱयऱों के लयऱ भारत में हसि्टरेक्टमी प्रकुरयऱ तब अपनऱई जातऱ है जब अन्य उपचार वकऱल हो जाते हैं ।
- यह कैंसर के ऊतकों को हटाने के लयऱ और गंभीर शरोणा दरद के मामलों में कैंसर के उपचार के हसऱसे के रूप में भी उपयोग कयऱ जातऱ है ।

भारत में हसि्टरेक्टमी से संबंघतऱ मुददे:

युवा महलाओं में हसि्टरेक्टमी का बढ़तऱ प्रचलनः

- हाल ही में सर्वोच्च नुयायालय के नरऱणय ने इस बात पर प्रकाश डालऱ कवऱकऱसतऱ देशों में हसि्टरेक्टमी के मामलों में आमतौर पर 45 वर्ष और उससे अधकऱ उमर कऱ प्रीमेनोपॉज़ल (रजोनवृत्तऱ के आसपास) महलाएँ शामिल होती हैं ।
- हालाँकऱ भारत में हसि्टरेक्टमी के मामले में समुदाय-आधारतऱ अधययनों में 28-36 वर्ष कऱ युवा महलाओं कऱ बढ़तऱ संखुया दरज कऱ गई है ।

NFHS डेटऱ:

- राष्टुरीय परवार सवासुथय सर्वेकषण (NFHS)-5 के सबसे ताज़ऱ अनुभवजन्य आँकड़ों के अनुसार, 15-49 वर्ष कऱ 3 प्रतऱशऱत महलाओं ने हसि्टरेक्टमी प्रकुरयऱ को अपनऱयऱ ।
- हसि्टरेक्टमी का प्रचलन आंधर प्रदेश (9 प्रतऱशऱत) में सबसे अधकऱ है । इसके बाद 15-49 आयु वर्ग कऱ महलाओं में तेलंगानऱ (8 प्रतऱशऱत), सकऱकमऱ (0.8 प्रतऱशऱत) और मेघालय (0.7 प्रतऱशऱत) में सबसे कम है ।
- हसि्टरेक्टमी का प्रचलन दकषऱणी कषेत्र में सबसे अधकऱ थऱ यऱनी 4.2 प्रतऱशऱत जो राष्टुरीय प्रचलन से भी अधकऱ थऱ । इसके बाद भारत के पूरुवी भाग (3.8 प्रतऱशऱत) का सुथान थऱ ।
- दूसरी ओर, सबसे कम वुयापकतऱ पूरुवोत्तर कषेत्र में देखी गई यऱनी केवल 1.2 प्रतऱशऱत ।

■ अनावश्यक हसि्टरेक्टमी:

- वर्ष 2013 में दायर एक [जनहति याचिका \(PIL\)](#) ने "अनावश्यक हसि्टरेक्टमी" के मुद्दे पर प्रकाश डाला।
- जनहति याचिका में खुलासा किया गया कि **बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान** राज्यों में महिलाओं को हसि्टरेक्टमी के अधीन किया गया था, जिसको अनावश्यक माना गया क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा था।
 - नजी अस्पताल इन अनावश्यक हसि्टरेक्टमी में संलग्न रहे थे। **दो-तर्हई से अधिक (70%) महिलाएँ, जो हसि्टरेक्टमी से गुज़री जनिका ऑपरेशन नजी स्वास्थ्य सुविधा में किया गया था।**
- प्रक्रिया का दुरुपयोग भी देखा गया था, स्वास्थ्य सेवा संस्थानवभिनिन [सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं](#) के अंतर्गत उच्च बीमा शुल्क का दावा करने के लिये इसका लाभ उठाते थे।

समस्या का समाधान करने के लिये प्रयास:

■ सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश:

- जनहति याचिका के प्रत्युत्तर में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे केंद्र द्वारा तैयार किये गए स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों को लागू करें ताकि अनावश्यक हसि्टरेक्टमी की नगिरानी और रोकथाम की जा सके। इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में **तीन महीने की समय-सीमा** में अनिवार्य किया गया था।
- अनावश्यक हसि्टरेक्टमी कराने वाली महिलाओं के **मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन** हुआ।
- इस निर्णय में यह स्वीकार किया गया कि **स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21** के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। सभी पहलुओं की सराहना करने के लिये जीवन, अच्छी स्वास्थ्य स्थितियों पर आधारित होना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने समस्या से निपटने के लिये एक कार्ययोजना का भी अनुरोध किया है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तरीय हसि्टरेक्टमी नगिरानी समिति बनाने तथा एक शिकायत पोर्टल की शुरुआत करने के सुझाव शामिल हैं।

■ स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश:

- वर्ष 2022 में **स्वास्थ्य मंत्रालय** ने अनावश्यक हसि्टरेक्टमी को रोकने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किये। इस प्रक्रिया का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये राज्यों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।
 - हाल ही में मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे **चिकित्सा संस्थानों द्वारा की जाने वाली हसि्टरेक्टमी पर डेटा साझा करें।**
 - **मातृ मृत्यु दर** के लिये किये गए **मौजूदा ऑडिट** के समान सभी हसि्टरेक्टमी प्रक्रिया के लिये अनिवार्य ऑडिट की भी सलाह दी गई थी।

स्रोत: द हिंदू